

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

5
०५/२०१३
फोन नं० ०६१२-२२१९५४ (का०)
फैक्स नं०-०६१२-२२१८९००
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :-

1-05-2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-5-05/2013 में आवेदक श्री मनोज कुमार, पिता-स्व० सबाब लाल, सा०-रानीपुर, पो०+थाना- फुलवारीशरीफ, जिला-पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक-21.05.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि उनका फुलवारीशरीफ में एक सामान्य मिठाई की दुकान है। उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-648/गो०, दिनांक-24.04.2013 द्वारा आवेदक का अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र अधिनस्थ पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आलोक में मात्र अग्रसारित किया गया है, अनुशंसा अंकित नहीं है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ द्वारा उक्त अनुज्ञप्ति प्रपत्र को जाँच के क्रम में पाया गया कि आवेदक श्री मनोज कुमार की मिठाई की दुकान है और इन्हें कोई आसन्न खतरा नहीं है, जिसके कारण थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ के द्वारा रिवाल्वर एवं पिस्टल की अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा नहीं की गयी है। थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक का पक्का छत का मकान है। आवेदक का सामान्य मिठाई दुकान है। इनकी गतिविधि ज्यादा सक्रिय नहीं है। जाँच के दौरान इनके जान-माल को कोई Immiennt Threat नहीं पायी गयी है। आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। साथ ही थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका-10 के सभी बिन्दुओं पर नहीं प्रतिवेदित किया गया है।

आवेदक के द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर कार्रवाई लंबित रहने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी० सं०-23388/2012 दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक-04.01.2013 को आदेश पारित करते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर विचार करते हुए चार माह के अंदर अंतिम आदेश पारित करने का निदेश दिया गया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं०-V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक-31.03.2010 की कंडिका-II में एन०पी०बोर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में निदेश अंकित है, जो निम्नवत है :-

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally.

कंडिका-II की उप कंडिका-b तथा e निम्नवत है :-

b) No licence may be granted without police verification, which will include report on i) antecedents of the applicant, ii) assessment of the threat, iii) capability of the applicant to handle arms, and iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence.

- 2 - 5/2013

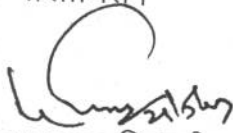
e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under section 13 (2) before granting arms licenses and no arms licence may be issued without police verification.


वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं०-V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक-31.03.2010 में निहित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक श्री मनोज कुमार को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, तथा गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं०-V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक-31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री मनोज कुमार, पिता-स्व० सबाब लाल, सा०-रानीपुर, पो०+थाना-फुलवारीशरीफ, जिला-पटना के आवेदित एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


जिला दण्डाधिकारी,
पटना।


जिला दण्डाधिकारी,
पटना।